

17

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा  
प्रकाश क्रमांक R. 887-तीन/14

होरालाल यादव तनय श्री गंगा प्रसाद यादव उमे 35 साल निवासी महसुआ  
तहसील रायपुर कर्छी जिला रीवा म०प्र० ..... निगरानी कर्ता

बनाम

- 1- शासन म०प्र० द्वारा प्रभारित तहसीलदार रायपुर कर्छी जिला रीवा
- 2- शान्ति साहू बत्नी सूर्यदीन साहू वर्तमान सरपंच ग्राम प्रवायत महसुआ टिकुरी  
टोला विकास छण्ड रायपुर कर्छी जिला रीवा म०प्र०

गैर निगरानी कर्ता

निगरानी कर्ता आदेश अवर आरुपित महोदय रीवा  
संभाग रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक 215/अपील/13-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता  
सन 1959 ई०

887-11/14

हस्ताक्षर श्री. यादव  
आज दिनांक... 17-12-2014 को  
किया गया

सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 455  
जिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
को प्राप्त

जिला मण्डल म० प्र० ग्वालियर

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

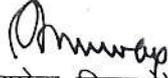
निगरानी प्रकरण क्रमांक : 887/III/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	जिला रीवा पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.4.2014	<p>यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 215/13-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 01-02-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक के अभिभाषक के अनुसार भूमि सर्वे नंबर 204 पर आवेदक का मकान बना है जबकि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 01-02-2014 में आये तथ्यों अनुसार सर्वे नंबर 204 की भूमि शासकीय है जिस पर आवेदक द्वारा झोंपड़ी (घॉस-फूस की) बनाकर तंत्र विद्या करना एवं तांत्रिकों को इकट्ठा करके शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। सर्वे नंबर 204 की भूमिशाला भवन हेतु आरक्षित है एवं इसी के अंशभाग पर आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसके कारण तहसीलदार ने आवेदक का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है और आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर कर्चु0 के समक्ष अपील</p>	

२- ४४७-आए/१५रीका  
दस्तावेज / शासन शास्त्री लालू

की, अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 2/अ-68/11-12 में पारित आदेश दिनांक 22-1-14 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखा है, जिसके कारण अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील निरस्त की है।

4/ उपरोक्त कारणों से आवेदक शासकीय भूमि, जो शाला भवन की है, पर अतिक्रमणकर्ता होने से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का पात्र नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

  
(अशोक शिवहरे)  
सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर